दैनिक जागरण
प्रत्येक संकट में एक अवसर भी छिपा होता है

कश्मीर की बाधा

यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में कश्मीर की चर्चा करते हुए यह कहा कि जो लोग विकास की राह में अवरोध और नफरत फैलाना चाहते हैं उनके नापाक इरादे कामयाब होने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री की ओर से ऐसे किसी बयान की आवश्यकता इसलिए थी, क्योंकि एक तो इन दिनों कश्मीर चर्चा के केंद्र में है और दूसरे, केंद्र सरकार से यह अपेक्षा बढ़ गई है कि वह घाटी को पटरी पर लाने के लिए हरसंभव उपाय करे। पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार ऐसे संकेत दे रही है कि वह कश्मीर की जनता को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ उसकी ओर से कश्मीर में व्याप्त अलगाववाद एवं आतंकवाद की कमर तोड़ने की भी प्रतिबद्धता जताई जा रही है। विचित्र यह है कि कुछ लोगों को केंद्र सरकार की यह प्रतिबद्धता रास नहीं आ रही है। ऐसे लोगों में घाटी में असर रखने वाले राजनीतिक दल भी हैं। इन दलों के नेताओं की ओर से जैसे बयान दिए जा रहे हैं उन्हें देखकर उनमें और अलगाववादियों में भेद करना कठिन हो रहा है। इन नेताओं ने कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाए जाने को जिस तरह अनुच्छेद 35-ए हटाने की कथित कवायद से जोड़ दिया उससे यही संकेत मिला कि उनके भरोसे घाटी को सही राह पर लाना मुश्किल है।

फिलहाल यह कहना कठिन है कि अनुच्छेद 35-ए और 370 को हटाने के बारे में किसी तरह का कोई फैसला होने जा रहा है या नहीं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इन अनुच्छेदों से जुड़े प्रावधानों ने जम्मू-कश्मीर और विशेष रूप से घाटी का अहित ही किया है। चूंकि अनुच्छेद 370 अलगाववाद का परिचायक बन गया है इसलिए कश्मीर को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ना और मुश्किल हो रहा है। विडंबना यह है कि अलगाववादियों के साथ कुछ राजनीतिक दल इस मुश्किल को बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। उनकी मानें तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला तत्व अनुच्छेद 370 ही है। क्या इससे वाहियात बात और कोई हो सकती है? क्या कश्मीरियत किसी संवैधानिक प्रावधान की उपज है और वह भी ऐसा प्रावधान जो अस्थाई है? उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की ओर से अनुच्छेद 35-ए एवं 370 को लेकर जैसे उत्तेजक बयान दिए जा रहे हैं उनसे यही स्पष्ट होता है कि ऐसे नेता कश्मीर को अपनी जागीर मान चुके हैं। इस मुगालते को दूर किया ही जाना चाहिए। बेहतर यह होगा कि केंद्र सरकार कश्मीर के विकास में बाधक बन रहे तत्वों से निपटने के साथ ही उनकी पोल खोलने का भी काम करे।

अपराध पर लगाम जरूरी

बिहार में अपराध पर लगाम के लिए उच्चस्तरीय बैठक और निर्देशों के बाद भी आए दिन हो रही वारदात चिंता का विषय है। इस पर गंभीरता से मंथन की जरूरत है, ताकि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। मुजफ्फरपुर में एक कुरियर कंपनी के कर्मियों से लूट की घटना बताती है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। अपराध समीक्षा में भी यह बात बार-बार उठी है कि पुलिस का सूचना तंत्र मजबूत हो। इलाके में गश्त बढ़ाई जाए, लेकिन इस तरह की वारदात दिनदहाड़े हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अपराधियों ने छपरा में भी एक कपड़ा व्यवसायी को गोली मारकर छह लाख रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया। आश्चर्य तो यह कि व्यवसायी ने करीब दस मिनट तक बदमाशों का विरोध किया और जूझते रहे, लेकिन वहां खड़े लोग तमाशबीन बने रहे। सुपौल में अपराधियों ने एक कपड़ा व्यवसायी के कर्मी से 1.20 हजार लूट लिया। ये घटनाएं पुलिस गश्त पर भी सवाल हैं। मुख्यमंत्री ने अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए सख्त कदम भी उठाए गए हैं। पुलिस मुख्यालय से भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीपी खुद थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद भी बीच शहर में इस तरह की वारदातें हो रही हैं तो कहीं-न-कहीं निचले स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है और निर्देशों की अनदेखी की जा रही है। पुलिस तंत्र को निचले स्तर पर कसने की जरूरत है। जिन इलाकों में वारदातें थम नहीं रहीं, वहां सख्त कार्रवाई करते हुए कड़े संदेश देने होंगे। जेल से छूटे या अब तक गिरफ्त से बाहर अपराधियों की गहन निगरानी जरूरी है। थाना स्तर पर पुलिस गश्त को और चुस्त-दुरुस्त करना होगा। ज्यादातर जगहों पर इसकी स्थिति ठीक नहीं है। इसका भी आकलन करना होगा कि क्षेत्र विशेष के लिहाज से मानव बल की कहां कितनी जरूरत है और इसकी पूर्ति करनी होगी। पुलिस को संसाधन भी मुहैया कराने होंगे। पुलिस मुख्यालय ने वरीय पदाधिकारियों तक के लिए निर्देश जारी कर रखा है कि वे अनुमंडल और अंचल स्तर तक खुद कैंप कर अपराध की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आए दिन हो रही वारदातों से आम जन का दहशत में आना स्वाभाविक है। पुलिस और कानून-व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। लोग कहीं भी बेखौफ आ-जा सकें, यह सुनिश्चित करना होगा।

भारत की मुश्किलें बढ़ाते ट्रंप

ब्रह्मा चेलानी

19 साल पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान से जिस तालिबान को उखाड़ फेंका उसे फिर सत्ता की कमान सौंपने की तैयारी कर रहा है। यह भारत के लिए भी खतरे की घंटी है

तालिबान के साथ 'शांति' समझौते की बेचैनी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस क्रूर संगठन के आका पाकिस्तान के आगे झुकने को तैयार हैं। अमेरिका के बदले रवैये में यह स्पष्ट भी हुआ जब उसने इस्लामाबाद के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से छह अरब डॉलर के राहत पैकेज का रास्ता साफ कर दिया। एक प्रमुख बलूच अलगाववादी धड़े को 'आतंकी' समूहों की सूची में डाल दिया। इसके अलावा ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच वार्ता का शिगूफा भी छेड़ा जिसमें कश्मीर में मध्यस्थता की पेशकश भी शामिल थी। पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारत के खिलाफ अमेरिका से मिले एफ-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया। फिर भी अमेरिका ने पाकिस्तान के एफ-16 बेड़े की मदद के लिए 12.5 करोड़ डॉलर की राशि मंजूर कर दी। तिस पर कहा कि इससे 'क्षेत्रीय संतुलन' के समक्ष कोई खतरा उत्पन्न नहीं होगा। कश्मीर विवाद में मध्यस्थता को लेकर ट्रंप ने जो विवादित बयान दिया वह पाकिस्तानी फौज समर्थित प्रधानमंत्री इमरान खान की मौजूदगी में दिया था। इस दौरान वह भारत और पाकिस्तान को बड़े विचित्र ढंग से एक तराजू में तौलते नजर आए। वहीं अफगानिस्तान से बाहर निकलने को लेकर वह एक तरह पाकिस्तान से गुहार लगाते दिखे।

बहरहाल कश्मीर विवाद में मध्यस्थता वाले बयान से ज्यादा हमारे लिए यह और बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए कि आखिर अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी को लेकर ट्रंप किस अंदाज में पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। तालिबान से समझौते को लेकर ट्रंप जैसी सौदेबाजी में जुटे हैं वह भारत के क्षेत्रीय हितों और आंतरिक सुरक्षा विशेषकर कश्मीर के लिए बेहद खतरनाक है। वहीं इस्लामाबाद ट्रंप प्रशासन से अफगानिस्तान में मदद के बदले कश्मीर विवाद में भूमिका और भारत-पाक के बीच बंद पड़ी वार्ता को फिर से बहाल कराने की उम्मीदें लगाए हुए हैं। ऐसे में यह महज कोई संयोग नहीं था कि ट्रंप ने इमरान खान की मौजूदगी में ही कश्मीर को लेकर बयान दिया।

भारत को ट्रंप के बयान पर हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत ने ही बालाकोट हमले के बाद उपजे तनाव में ट्रंप को दखल देने की छूट दी। याद रहे कि भारत-पाक में तनाव घटने की घोषणा पीएम मोदी ने नहीं, बल्कि ट्रंप ने की थी। बालाकोट बाजी पलटने वाला पड़ाव था। हालांकि 27 फरवरी को पाक के हवाई हमले के बाद पलटवार में नाकाम रहे भारत के हाथ से वह निर्णायक मौका फिसल गया। इससे भी बदतर बात यह रही कि उसने ट्रंप जैसे अहंकारी नेता को इसमें टांग अड़ाने और तनाव घटाने का श्रेय लेने दिया। इसके बाद बंधक भारतीय पायलट की वापसी की राह खुली। कारगिल युद्ध के समय भी भारत ने अमेरिकी कूटनीतिक हस्तक्षेप होने दिया था। कड़वी हकीकत यही है कि भारत कभी भी पाक के साथ विवादों का निर्णायक पटाक्षेप नहीं कर पाया। भले ही हालात भारत के हक में हों, लेकिन वह इन मौकों का लाभ नहीं उठा पाया। जैसे 1972 के शिमला समझौते में भी भारत 93,000 युद्ध बंदियों के बदले कश्मीर मुद्दे, सीमा विवाद और करतारपुर पर सौदेबाजी कर सकता था। तुरुप के सारे पत्ते होने के बावजूद भारत बाजी नहीं जीत पाया। जंग के मैदान में सैनिकों की पूंजी को वार्ता की मेज पर लुटा दिया गया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 जुलाई को कहा कि पाकिस्तान की भारत के साथ कोई पूर्ण या सीमित युद्ध लड़ने की हैसियत नहीं और यही वजह है कि वह छद्म युद्ध में लगा हुआ है। उनकी बात एकदम दुरुस्त है। मगर यह भी सही है कि भारत पाक के साथ अपने विवादों को निपटाने में हिचक दिखाता है। भारत पाक को आतंकी देश बताता तो है, लेकिन नीतिगत रूप से इसे पुष्ट नहीं करता। इस सबसे छद्म युद्ध के लिए पाकिस्तान का हौसला और मध्यस्थ बनने के लिए अमेरिका की हसरत हिलोरे मारती है। ट्रंप जिस तरह पाकिस्तान-तालिबान की खुशामद में जुटे हैं वह भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि यह भारत के क्षेत्रीय और सुरक्षा हितों के प्रतिकूल है। इसके अलावा ट्रंप के और भी कदम भारत की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। फिर चाहे ईरान से तेल आयात पर प्रतिबंध लगाकर भारत पर बोझ बढ़ाना हो या भारत को मिला जीएसपी दर्जा समाप्त करना या भारत से कुछ रियायतें हासिल करने के मकसद से व्यापार युद्ध में जुटना।

इससे पहले मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर भी ट्रंप पाक की पीठ थपथपा चुके हैं। पाक में छुट्टा घूमने और रैलियों में खुलेआम जिहाद के लिए भड़काने के बावजूद एक करोड़ डॉलर के इनामी आतंकी पर ट्रंप ने 17 जुलाई को ट्वीट किया, 'दस साल की खोजबीन के बाद पाकिस्तान ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। उसके लिए बीते दो साल में भारी दबाव डाला गया।' एक वक्त अल कायदा को पनाह देने वाला और अब दुनिया के दुर्दांत आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे तालिबान से अमेरिका न केवल अपनी सेनाओं की वापसी का वादा, बल्कि काबुल की सत्ता तक पहुंचने का मैदान मुहैया करा रहा है। पाकिस्तानी सैन्य जनरल यह दिखा रहे हैं कि आतंक को शह देना कितना फलदायी होता है। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे उनके पिट्ठू अफगानिस्तान में अमेरिका जैसे देश को उनकी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसमें भी निर्णायक सौदे के लिए अमेरिका को मदद के लिए पाकिस्तान का मोहताज बनना पड़ रहा है। तालिबान-पाकिस्तान के साथ ट्रंप प्रशासन का संभावित समझौता भारत विरोधी पाकिस्तानी आतंकी संगठनों लश्कर और जैश का हौसला बढ़ाएगा। हालांकि इससे सबसे ज्यादा उस कुख्यात आइएसआइ के मंसूबे परवान चढ़ेंगे जो ऐसे तमाम आतंकी संगठनों को पैदा करती रही है।

इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अमेरिका एक बार फिर युद्ध पीड़ित अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है। बिल्कुल वैसे जैसे तीन दशक पहले सोवियत सेनाओं को वहां से खदेड़कर निकला था। उस सफलता ने बड़े विरोधाभासी ढंग से अफगानिस्तान को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। उस अभियान में अमेरिका का साथ देने वाली आइएसआइ ने बाद में तालिबान को सत्ता में स्थापित करा दिया। क्या अमेरिका अफगानिस्तान में पाक को फिर से वैसा ही खुला हाथ देगा। यदि ऐसा हुआ तो महिला एवं नागरिक अधिकारों के मोर्चे पर जो भी प्रगति हुई है वह हवा हो जाएगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि तालिबान उन्हीं सख्त मध्यकालीन परंपराओं को थोपेगा जो उसने 1996 से 2001 के बीच अपने शासन में थोप रखी थीं। इससे पाकिस्तान में इस्लामी चरमपंथियों की ताकत बढ़ेगी।

अमेरिका के लिए वक्त का पहिया घूमकर फिर वहीं आ गया है। लगभग 19 साल पहले उसने जिस तालिबान को उखाड़ फेंका था उसे ही एक बार फिर सत्ता की कमान सौंपने की तैयारी कर रहा है। हेनरी किसिंग्जर ने एक बार कहा था कि 'अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती और घातक होती है।' भारत उनके बयान की तपिश शिद्दत से महसूस कर रहा है।

(लेखक सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

संसाधनों की कमी से जूझते विश्वविद्यालय

प्रो. सुरेंद्र प्रताप सिंह

सरकार ने यदि अपना दिल बड़ा नहीं किया तो उच्च शिक्षा का मुरझाता पौधा बिल्कुल सूख भी सकता है

बीते दिनों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में नई शिक्षा नीति के पुनर्गठन के लिए एक मसौदा नीति प्रस्तुत की थी। उसके बाद से ही इस पर बहस शुरू हो गई है कि नए भारत में हमारी शिक्षा नीति कैसी हो? वह नीति जो सबके साथ सबका विकास कर सके। मैं अपने 42 वर्ष के अनुभव के तौर पर यह मानता हूं कि नीतियों में एकरूपता और स्पष्टता होनी चाहिए तभी हमारी उच्च शिक्षा गुणवत्ता युक्त हो सकेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। देश में मोटे तौर पर तीन तरह के विश्वविद्यालय हैं-राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और सम (डीम्ड) विश्वविद्यालय। और ये तीनों अलग-अलग नियमों से संचालित होते हैं। राज्य विश्वविद्यालय भी तीन जगहों से निर्देशित होते हैं। पहला है अध्यादेश और अधिनियम से, दूसरा है सरकारी आदेश से और तीसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से। शिक्षा को कभी एक व्यवसाय के रूप में या लाभ कमाने वाले संस्थान के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि इसे एक सामाजिक निवेश माना जाता रहा है, पर पिछले दशकों में इस नजरिये में बदलाव आया है। आप किसी भी हाईवे या शहर से गुजरें तो आपको लुभावने वादे करते शैक्षिक संस्थानों के बड़े-बड़े बोर्ड दिखेंगे, पर उनके वायदों को जांचने-परखने का कोई उपकरण हमारे पास नहीं है। इसीलिए वहां से विद्यार्थी नहीं पेशेवर निकल रहे हैं, जिसका असर समाज की सामाजिकता पर पड़ रहा है और संवेदनशीलता में कमी आ रही है।

हर गली-मोहल्ले में खुलने वाले इन संस्थानों के पीछे संबद्धता का जिन्न जिम्मेदार है। उदाहरण के तौर पर कानपुर विश्वविद्यालय से 1100 और आगरा विश्वविद्यालय से 1035 कॉलेज संबद्ध हैं। ऐसे में अच्छे और पुराने डिग्री कॉलेजों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इसके अलावा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को भी बढ़ावा दिया ही जाना चाहिए। विश्वविद्यालय खुद पाठ्यक्रम बनाएं और परीक्षा करवाएं। इससे उनके ऊपर से बोझ कम होगा और वे शोध पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। अभी सिर्फ परीक्षा एवं परिणाम निकालने में ही समय निकल जाता है। स्वायत्तता को बढ़ावा दिया जाए और पुराने विश्वविद्यालयों को संबद्धता से मुक्त किया जाए जिससे वे अपनी पहचान शोध और शिक्षा के क्षेत्र में बना सकें। दुनिया के जितने भी सर्वश्रेष्ठ संस्थान या विश्वविद्यालय हैं, वे संबद्धता नहीं देते हैं और उन्हें सरकार के साथ-साथ समाज के हर तबके से आर्थिक सहयोग मिलता है। अब हमें भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध पर जोर देना होगा। साथ ही शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी होनी चाहिए, ताकि शिक्षण पर जोर रहे। पाठ्यक्रम में बदलाव उद्योगों की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि उच्च शिक्षा की सर्वोच्च नियामक संस्था बार-बार अपने नियमों में बदलाव कर रही है जो यह दिखाता है कि हमारी शिक्षा के आदर्श स्वरूप में स्पष्टता नहीं है। उदाहरण के तौर पर छठा वेतनमान 2006 में लागू हुआ तो नियमन 2010 में आया। उत्तर प्रदेश में यह नियमन 2014 में लागू हुआ। इसी तरह सातवें वेतनमान का नियमन 2018 में आ गया। उत्तर प्रदेश में यह अब लागू होगा। बार-बार केंद्रीय नीति बदलने से शिक्षकों की नियुक्ति, प्रोन्नति, छुट्टी आदि के नियम राज्य सरकारों द्वारा उसके अनुरूप बदलाव करने में वर्षों लग जाते हैं। इससे वाद-प्रतिवाद बढ़ते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बने और सभी राज्य उसे लागू करें। अभी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र और कुलपतियों के कार्यकाल की सीमा भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। ऐसे में भी राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति की आवश्यकता है जो सभी के लिए एक जैसी हो। केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, पर उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में यह तीन साल का है।

दूसरी ओर विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। यहां करीब 31 प्रतिशत पद खाली हैं। यूजीसी के 200 प्वाइंट रोस्टर नियम को लागू किया गया है। इसके अनुसार अब विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर आरक्षण लागू होगा। पहले विभाग स्तर पर आरक्षण लागू होना था। वहीं गरीब सवर्णों को आरक्षण देने पर अभी तक राज्य निर्णय लागू नहीं करवा पाए हैं। ऐसे में नियुक्ति की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात धन की है जिनसे सरकारों ने लगातार हाथ खींचे हैं। विश्वविद्यालयों के पास विद्यार्थियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए धन नहीं हैं। सौ साल पुराने लखनऊ विश्वविद्यालय में हर साल शिक्षक एवं कर्मचारियों के वेतन पर 147 करोड़ रुपये खर्च होते हैं और राज्य सरकार 34 करोड़ रुपये की ही मदद दे पाती है। सरकार को उच्च शिक्षा के लिए अपना दिल बड़ा करना होगा, क्योंकि प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का संकुल अभी भी सरकारी विश्वविद्यालयों के ही पास है। अगर सरकार निवेश नहीं करेगी तो यह पौधा जो अब मुरझा रहा है, बिल्कुल सूख भी सकता है।

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एकसमान पाठ्यक्रम लागू किया जाए और यूजीसी के निर्देश के अनुसार दस प्रतिशत पाठ्यक्रम स्थानीय जरूरतों के आधार पर शामिल किया जाए। यूनिवर्सिटी स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू करें और नकल पर सख्ती करें। स्नातक में परीक्षा में बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएं जिससे छात्र पूरा कोर्स पढ़ने को मजबूर होंगे और समय पर परीक्षा परिणाम भी घोषित हो सकेगा। विश्वविद्यालयों में छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित करना होगा। उद्योग जगत की जरूरत के अनुसार कोर्स डिजाइन किया जाना जरूरी है। प्रोफेशनल कोर्स तो इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा करने वाले जरूर होने चाहिए। उद्योग जगत के विशेषज्ञ, बड़े उद्यमी, वैज्ञानिक, साहित्यकार और अर्थशास्त्री इत्यादि के व्याख्यान नियमित रूप से आयोजित किए जाएं। सेंट्रल प्लेसमेंट सेल बनाकर विद्यार्थियों को अधिक से अधिक रोजगार हासिल करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय न सिर्फ अच्छे संस्थानों से गठजोड़ कर साझा शोध करें, बल्कि विभागों के बीच भी प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ाएं। इसके साथ ही विद्यार्थियों से जुड़ी सुविधाएं अधिक से अधिक ऑनलाइन करने पर जोर देना चाहिए।

(लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आदर

आदर की भावना से हृदय की पवित्रता, बुद्धि की निर्मलता एवं स्वभाव की उत्कृष्टता का परिचय मिलता है। व्यक्ति आदर देकर ही आदर पाने का पात्र बनता है। आज्ञा-पालन और अभिवादन आदर देने की महत्वपूर्ण विधा हैं। इससे व्यक्ति के नैतिक रूप से सुंदर, उन्नत चरित्र के बारे में ज्ञात होता है। वहीं उदंडता स्वभाव को पतनोमुख बना डालती है। इसके प्रभाव से समाज-संस्कृति विकृत हो जाती है। उदंड लोग अनादर करने में ज्यादा रुचि लेते हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट बनी रहती है।

वास्तव में आदरणीय व्यक्ति को आदर देने से व्यक्ति के शुभ-संस्कार में वृद्धि होती है। चेतना का परिष्कार होकर मन आनंदित होती है। जब व्यक्ति अपने मित्र, कुटुंब, बड़े-बुजुर्ग, गुरु, अभिभावक को आदर देता है तो आदर देने वाला और आदर पाने वाला, दोनों बहुत ही लाभान्वित होते हैं। सर्वप्रथम दोनों के मन-हृदय प्रफुल्लित, उल्लासित हो जाते हैं। मन की गंदगियों का सफाया हो जाता है। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा-तरंग का सृजन होकर सृजनात्मक विचारों, पहलुओं में वृद्धि होती है। सकारात्मकता का भाव ही व्यक्ति को आदर देने के लिए उत्प्रेरित करता है और नकारात्मक भाव की वृद्धि होने से अनादर की भावना कूट-कूटकर मन, विचार में भर जाती है। आत्मा निष्पाप और निष्कलंक होती है, लेकिन वातावरण के दोष-प्रभाव से व्यक्ति की चेतना, विचार कुछ समय के लिए बीमार हो जाते हैं, पर ज्यों ही उन्हें सत्संग का अवसर प्राप्त होता है तो विषाक्तता का निवारण होता है और उनके हृदय में प्रेम की गंगा बह चलती है और व्यक्ति के स्वभाव में आदर देने की लालसा प्रबल हो जाती है।

जाहिर है जीवन में आनंद, खुशी की अभिवृद्धि तथा जीवन की सार्थकता के लिए, समाज में मित्रता की वृद्धि के लिए, सभ्यता, संस्कृति के उत्थान के लिए, समाज में शांति-सद्भाव की ज्योति प्रखर करने के लिए आदर देने की भावना को मनुष्य अपने अंदर विकसित करें। यही हमारी भारतीय परंपरा भी है। सभी को आदर दें।

मुकेश ऋषि

विकास का आधार है इनोवेशन

अमृत कुमार

जो देश इनोवेशन के क्षेत्र में आगे रहेंगे वे इसके परिणामस्वरूप आर्थिक और फिर सामाजिक विकास में भी अग्रणी रहेंगे

हाल ही में 130 देशों में किए गए एक अध्ययन के आधार पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 52वें स्थान पर रखा गया है। पिछले चार वर्षों के दौरान भारत इस सूची में 24 स्थान ऊपर उठा है। हालांकि इस मामले में भारत अपने पड़ोसी चीन से अभी भी काफी पीछे है। चीन इस मामले में 14वें स्थान पर है। सिंगापुर आठवें स्थान पर है। इजरायल जैसा छोटा देश भी शीर्ष दस देशों में शुमार है। जाहिर है भारत को शीर्ष दस देशों में आने के लिए अभी भी काफी कुछ करने की दरकार है।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 80 पैमानों पर तैयार जाता है जिसमें सृजनात्मक उत्पादन, संस्थाओं की गुणवत्ता, पूंजी निवेश, शिक्षा की गुणवत्ता आदि प्रमुख घटक हैं। हालांकि इनोवेशन यानी नवोन्मेष एक मानसिकता है, जिसके चलते कोई देश अपनी संस्थाओं और दूसरे संसाधनों का सृजनात्मक तरीके से उपयोग कर अलग तरीके के उत्पादों का निर्माण करता है। फिर उसे बाजार में उतार कर लोगों की जरूरतें पूरी करता है और आय कमाता है। यदि भारत के युवा इनोवेशन की मानसिकता से लैस हो जाएं तो हमारे देश के इस मामले में पीछे रहने का कोई कारण नहीं है। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए निवेश का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व इनोवेशन का भी होता है। पिछले कुछ वर्षों से एक तथ्य साफ उभर कर आया है कि जो देश शोध और विकास (आरएंडडी) पर जितना अधिक खर्च कर रहे हैं उसी के अनुपात में उनके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में जो भी देश आने वाले वर्षों में इनोवेशन के क्षेत्र में आगे रहेगा वह इसके परिणामस्वरूप तकनीकी और फिर सामाजिक-आर्थिक विकास में भी अग्रणी रहेगा। राहत की बात यह है कि भारत इस मामले में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

यद्यपि भारत इस सूची में ऊपर आने के लिए कई तरह के सुधारों को अंजाम दे रहा है जैसे कि पेटेंट कराने में लगने वाले समय को कम करने की कोशिश कर रहा है, अधिक से अधिक उच्च शिक्षण संस्थाएं खोल रहा है, स्कूलों में लैब स्थापित कर रहा है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। दूसरे मोर्चों पर भी सुधार की रफ्तार बढ़ानी होगी। यह ठीक है कि सरकार ने शोध कार्यों की फंडिंग के लिए एक केंद्रीयकृत निकाय गठित करने का फैसला किया है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है उसे देखना होगा कि शोध कार्यों के लिए फंड देने में नौकरशाही की तरफ से किसी तरह की कंजूसी तो नहीं दिखाई जा रही है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में ऐसा माहौल बनाना होगा ताकि वहां मुक्त सोच को बढ़ावा मिले। जाहिर है देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए शोध और विकास पर खर्च बढ़ाने के साथ-साथ हमें अपनी स्कूली शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा। स्वास्थ्य पर खर्च की सीमा बढ़ानी होगी। और तमाम सामाजिक रूढ़ियों को ध्वस्त करना होगा, ताकि हर क्षेत्र-वर्ग से नए विचार मुख्यधारा में जगह बना सकें।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

संवादहीनता की स्थिति बनाती क्लिष्ट हिंदी

डॉ. विजय अग्रवाल का लेख, 'संघ सेवा आयोग की हिंदी' अत्यंत प्रासंगिक है। भाषा प्रमुखतः संवाद के लिए होती है। ऐसी भाषा जिससे संवादहीनता की स्थिति बने अवांछित है। यह सत्य है कि बोलचाल की भाषा एवं साहित्यिक भाषा में अंतर होता है, परंतु साहित्यिक भाषा भी क्लिष्ट नहीं होती है। उसे भी एक सर्व साधारण व्यक्ति थोड़े से प्रयास से समझ सकता है, जिससे संवादहीनता की स्थिति पैदा नहीं होती है। एक भाषा के सभी शब्दों के समानांतर शब्द दूसरी भाषा में होना आवश्यक नहीं है। अतः हम अपनी भाषा की समृद्धि के लिए उन शब्दों के समानांतर शब्द अपनी भाषा में जोड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु इस प्रक्रिया में ऐसा नहीं होना चाहिए कि समानांतर बनाया गया शब्द इतना क्लिष्ट या अव्यावहारिक हो कि उसका अर्थ ही समझना कठिन हो जाए, उसके प्रयोग से संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो, जैसा कि लेखक ने अपने उदाहरणों में चित्रित किया है। 'ट्रेन' की हिंदी 'लौह पथ गामिनी' बनाने अथवा 'स्टेशन' की हिंदी 'लौह पथ गामिनी विश्राम स्थल' बनाने का क्या औचित्य है? ऐसी अवस्था में जब हम किसी अंग्रेजी शब्द का उपयुक्त सुगम हिंदी शब्द बनाने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं तो हमें उस शब्द को हिंदी में उसके उसी रूप में अपना लेना चाहिए। ऐसा सभी भाषा विद्वान करते हैं। जैसे 'जुगाड़' को अंग्रेजी ने इसके अपने मूल रूप में अपना लिया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं।

krishnam.agrawal@gmail.com

बदल रहा चीनी रुख

1962 में चीन ने खुद चीनी-हिंदी भाई-भाई कहकर धोखा दिया और हमसे युद्ध करके हमारी जमीन हड़प ली। हमारे शत्रु और उसके मित्र पाकिस्तान ने भी तीन बार युद्ध किया, किंतु हर लड़ाई में बुरी तरह मात खाई। चीन के मित्र पाक ने तीन-तीन बार मात खाने और आतंकवाद के मामले में अंतरराष्ट्रीय लताड़ मिलने और दोस्त चीन की भी संयुक्त राष्ट्र में नहीं चलने का नतीजा यह हुआ कि अब चीन का रुख भारत के प्रति नरम होता नजर आ रहा है। कहते भी हैं कि मुसीबत में कोई साथ नहीं देता, किंतु ताकत को दुनिया सलाम करती है।

mahesh_nenava@yahoo.com

इंसानियत के रिश्ते

मनुष्य जीवन का लक्ष्य सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं होता, बल्कि अपने कुछ फर्ज को पहचान कर उनको पूरा करना भी होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य तो सिर्फ हमारे परिवारवालों तक ही सीमित होगा, ऐसा नहीं है। हम सबके कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं जो न रिश्ते से जुड़े होते हैं न समाज से, वे तो केवल ऐसे फर्ज हैं जो हमें इंसानी रूप की परिभाषा बतलाते हैं। ईश्वर ने अनेकों मनुष्य इसलिए बनाए कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। सांसारिक कर्तव्य का अर्थ ही मदद है, बिना किसी नाम, धर्म, खून इत्यादि जाने। आजकल लोगो में इतनी स्वार्थ की भूख बढ़ गई है की वो इंसानियत के रिश्ते को भुला बैठे हैं।

nikitabedi1994@gmail.com

कश्मीर में और सैनिक

जम्मू कश्मीर में अर्द्ध सैनिक बलों की और तैनाती वहां शांति स्थापना एवं आतंकरोधी कार्रवाई के लिए उपयुक्त है, क्योंकि जब तक आतंक को कुचल नहीं दिया जाता तब तक शांति की बातें बेमानी हैं। इसलिए घाटी में सैन्य बलों की संख्या में वृद्धि एक अच्छा निर्णय है। आतंकवादियों के साथ जितना सख्ती से निपटा जाए उतना ही घाटी के आम लोगों को विश्वास में लेने के प्रयास भी तेज करने होंगे, ताकि विश्वास बहाली की जा सके और वहां के लोगों को लगे कि सैन्य बलों की तैनाती उनके हित के लिए जरूरी है।

cddetha@gmail.com

आजम का व्यवहार

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान का महिलाओं के प्रति गलत व्यवहार कोई नई बात नहीं है। चुनाव के समय जयाप्रदा पर की गई टिप्पणी पर आजम खान की चौतरफा आलोचना हुई थी। लेकिन अपनी आदत से मजबूर उन्होंने संसद के अंदर ही सभापति की कुर्सी पर बैठी महिला के साथ अन